बृहस्पतिवार
34 साल से देहरादून का विश्वास
03 सितम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 222
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

दूनवैलीमेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94
email: doonvalley_news@yahoo.com
Website: dunvalleymail.com
डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

‘शुद्धिकरण’ विवाद पहुंचा हाईकोर्ट!

❑रामलीला मैदान के शुद्धिकरण पर हाईकोर्ट की चौखट पर डा. बैजनाथ, सात सितंबर को होगी सुनवाई

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। हल्द्वानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शुद्धिकरण और हवन-यज्ञ के नाम पर परोसे गए नफरती खेल की आंच अब सीधे उत्तराखंड हाईकोर्ट के दरवाजे तक जा पहुंची है। सत्ता के नशे में चूर नेताओं की शह, खाकी की संदिग्ध खामोशी और प्रशासनिक लीपापोती का भांडाफोड़ करते हुए जनहित याचिका ने पूरी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। सात सितंबर को होने जा रही सुनवाई से पहले शासन-प्रशासन के शीर्ष आकाओं की नींद उड़ चुकी है और पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि हल्द्वानी के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जनसभा के बाद कथित तौर पर कराए गए शुद्धिकरण यज्ञ/हवन का विवाद अब उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। मामले में डा. बैजनाथ ने जनहित याचिका दायर कर पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र, निष्पक्ष और समयबद्ध जांच की मांग की है। याचिका पर 7 सितंबर को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई प्रस्तावित है। ई-कोर्ट रिकार्ड के अनुसार मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति जस्टिस सुभाष उपाध्याय की डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध है। डा. बैजनाथ की ओर से अधिवक्ता रक्षित जोशी पैरवी कर रहे हैं।

याचिका में अदालत से मांग की गई है कि खड़गे की सभा के बाद रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ/हवन की जांच स्थानीय थाने से जुड़े पुलिसकर्मियों के बजाय किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या ऐसी स्वतंत्र टीम से कराई जाए, जिसका स्थानीय पुलिस स्टेशन से संबंध न हो। यानी याचिका ने सीधे उस सवाल को अदालत के सामने ला खड़ा किया है कि आखिर सार्वजनिक राजनीतिक कार्यक्रम के बाद शुद्धिकरण कराने की जरूरत क्यों पड़ी और इस पूरी कवायद के पीछे वास्तविक मंशा क्या थी?

◆डा. बैजनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद शुद्धिकरण को दी हाईकोर्ट में चुनौती
◆स्वतंत्र जांच से लेकर साक्ष्य सुरक्षित रखने की मांग, पुलिस की भूमिका भी आ गई है सवालों के घेरे में
◆सत्ता के नशे में चूर नेताओं की शह, खाकी की संदिग्ध खामोशी और प्रशासनिक लीपापोती का भांडाफोड़
◆जनहित याचिका ने पूरी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी, कुर्सी बचाने में जुट गए हैं सूबे के आला अफसर

मामले की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि याचिका में जांच के दौरान यदि कानूनन अपराध के तत्व सामने आते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। डा. बैजनाथ की याचिका में अदालत से घटनाक्रम से जुड़े तमाम साक्ष्यों को तत्काल सुरक्षित रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। इसमें सीसीटीवी फुटेज, वीडियो रिकार्डिंग, फोटो, इलेक्ट्रानिक संचार, सोशल मीडिया सामग्री, पुलिस रिकार्ड, शिकायतें, रिपोर्ट, अनुमति संबंधी दस्तावेज और अन्य इलेक्ट्रानिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य शामिल हैं।

यह मांग मामले को महज राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जाती है। अब सवाल यह भी है कि घटना के समय क्या रिकार्ड हुआ, किसने क्या किया, प्रशासन और पुलिस को क्या जानकारी थी और बाद में पूरे घटनाक्रम पर क्या कार्रवाई हुई। याचिका में राज्य सरकार के साथ जिलाधिकारी, नैनीताल, एसएसपी नैनीताल, पुलिस महानिदेशक और संबंधित थाना प्रभारी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। इससे साफ है कि याचिकाकर्ता केवल घटना की जांच नहीं, बल्कि प्रशासन और पुलिस की भूमिका की भी न्यायिक निगरानी में पड़ताल चाहता है।

याचिका का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पक्ष यह है कि राज्य सरकार को उत्तराखंड में छुआछूत के संवैधानिक निषेध को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही राज्य के दायित्वों के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग भी अदालत से की गई है। यानी हल्द्वानी का यह विवाद अब केवल किसने हवन कराया और क्यों कराया तक सीमित नहीं है। याचिका ने इसे समानता, सामाजिक सम्मान और छुआछूत के खिलाफ संवैधानिक व्यवस्था के सवाल से जोड़ दिया है।

रामलीला मैदान में सामाजिक सौहार्द को तार-तार करने वाले इस विवादित घटनाक्रम पर अब तक पुलिस-प्रशासन मूकदर्शक बना तमाशा देख रहा था। नेताओं की चौखट पर नतमस्तक पुलिस जिस मामले में एफआईआर तक दर्ज करने से कतरा रही थी, उसी मामले को डा.

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

ऑपरेशन हॉटस्पॉट: साइबर अपराधियों पर एसटीएफ का शिकंजा

संवाददाता

देहरादून। उत्तराखण्ड पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट चलाते हुए 820 संदिग्ध बैंक खातों के भौतिक और डिजिटल सत्यापन के बाद 159 एफआईआर दर्ज किये।

एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड में पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के तहत एसटीएफ, साइबर क्राइम यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स और समस्त जनपद पुलिस द्वारा प्रदेशभर में 7 दिवसीय ऑपरेशन हॉटस्पॉट (24 अगस्त से 01 सितंबर, 2026) सफलतापूर्वक संचालित किया गया। इस विशेष अभियान का उद्देश्य साइबर ठगी करने वालों के साथ-साथ ठगी की रकम निकालने वालों और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने वाले पूरे साइबर क्राइम नेटवर्क/चेन को ध्वस्त करना था।

संदिग्ध बैंक खाते: 820 संदिग्ध बैंक खातों के भौतिक और डिजिटल सत्यापन के बाद 159 एफआईआर दर्ज की गईं। एटीएम निकासी : 1,236 स्थानों/मामलों के सत्यापन के बाद 32 एफआईआर दर्ज। चेक से निकासी : 84 स्थानों/मामलों के सत्यापन पर 37 एफआईआर दर्ज। संदिग्ध सिम- पॉइंट ऑफ सेल (सिम - पोस): फर्जी/अनियमित केवाईसी के जरिए सिम बेचने वाले 22 संदिग्ध सिम-पीओएस का सत्यापन कर 10 एफआईआर दर्ज। डिजिटल फुटप्रिंट्स ब्लॉक: साइबर अपराध में इस्तेमाल हो रहे 644 संदिग्ध सिम और 630 आईएमईआई ब्लॉक किए गए। इसके अलावा 442 मामलों का सत्यापन कर 10 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए। समन्वय पोर्टल से मैपिंग: पूर्व में गिरफ्तार 240 साइबर अपराधियों की मैपिंग के जरिए देशभर में 100 से अधिक अन्य साइबर अपराधों में उनकी संलिप्तता का खुलासा हुआ। हरिद्वार में 'नवादा ग्रुप' का पर्दाफाश: हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क नवादा ग्रुप के 05 सदस्यों को गिरफ्तार किया। तकनीकी जांच में इस नेटवर्क से जुड़े 200 से अधिक बैंक खाते सामने आए, जिनका इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया जा रहा था। इनके पास से 45 एटीएम कार्ड, 20 पासबुक, 2 लैपटॉप और 17 मोबाइल बरामद हुए। कोटद्वार में फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 3.86 लाख रुपये की ठगी के मामले में फरार इनामी आरोपी आशीष रिचर्ड को गिरफ्तार किया गया। जांच में उसके 8 बैंक खातों में लगभग 1.50 करोड़ के संदिग्ध लेन-देन का पता चला (जिसमें से 7 लाख फ्रीज किए जा चुके हैं)। इस आरोपी के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में 19 शिकायतें दर्ज हैं। एसटीएफ द्वारा जुलाई में अंतरराज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ा गया था जो नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों के खाते खुलवाकर ठगी की रकम ट्रांसफर करते थे। वहीं पथरी (हरिद्वार) पुलिस ने 5% कमीशन लेकर एटीएम से साइबर ठगी का कैश निकालने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

◆820 संदिग्ध बैंक खातों की जांच, 159 एफआईआर दर्ज
◆10 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 644 सिम और 630 आईएमइआई ब्लॉक
◆240 पुराने साइबर अपराधियों की मैपिंग से 100 केसों का खुलासा

▶▶ शेष पृष्ठ 2 पर

दून वैली मेल

संपादकीय

श्रद्धालु की श्रद्धा का अंश

अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहां चढ़ने वाला हर रुपया केवल मुद्रा नहीं, बल्कि किसी श्रद्धालु की श्रद्धा का अंश है। इसलिए मंदिर के चढ़ावे में चोरी की खबरें सामने आना महज एक आपराधिक घटना नहीं मानी जा सकतीं। यह उस भरोसे पर चोट है, जिसके सहारे देश-दुनिया से श्रद्धालु रामलला के दरबार में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। चढ़ावे में चोरी के मामले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा पहली बार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ की नियुक्ति को इसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह फैसला देर से आया हो सकता है, लेकिन यदि इसका उद्देश्य मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पेशेवर, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है तो इसका स्वागत होना चाहिए। सवाल सिर्फ यह है कि क्या एक सीईओ की नियुक्ति से व्यवस्था बदल जाएगी? निश्चित रूप से नहीं। व्यवस्था पदों से नहीं, बल्कि व्यवस्था के भीतर जवाबदेही तय करने से बदलती है। राम मंदिर सामान्य धार्मिक संस्थान नहीं है। यह करोड़ों लोगों की भावनाओं का केंद्र है और यहां होने वाला आर्थिक लेन-देन भी सामान्य धार्मिक चढ़ावे से कहीं बड़ा है। ऐसे में दानपात्र से लेकर ऑनलाइन दान, नकद चढ़ावे से लेकर आभूषण, प्रसाद व्यवस्था से लेकर ट्रस्ट की संपत्तियों तक हर स्तर पर ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसमें किसी व्यक्ति की नीयत पर भरोसा करने के बजाय व्यवस्था की पारदर्शिता पर भरोसा किया जा सके। सबसे बड़ा सवाल यही है कि चढ़ावे की सुरक्षा और गिनती की प्रक्रिया कितनी वैज्ञानिक है? पैसा कहां से आता है, किस स्तर पर उसकी गिनती होती है, कौन उसका हिसाब रखता है, बैंक में कब जमा होता है और उसका ऑडिट कौन करता है। इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। मंदिर प्रशासन को यह मानकर चलना होगा कि पारदर्शिता श्रद्धा को कम नहीं करती, बल्कि श्रद्धा को और मजबूत करती है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लंबे संघर्ष, जनभावना और व्यापक सामाजिक सहभागिता के बाद हुआ है। ऐसे में मंदिर से जुड़ी किसी भी वित्तीय अनियमितता को सामान्य प्रशासनिक चूक कहकर टालना उचित नहीं होगा। राम के नाम पर आया एक-एक पैसा सार्वजनिक विश्वास की संपत्ति है। उसकी निगरानी में यदि कहीं छेद है तो उसे तत्काल बंद करना मंदिर प्रशासन की नैतिक जिम्मेदारी है। सीईओ की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे मंदिर प्रबंधन को धार्मिक व्यवस्था के साथ आधुनिक प्रशासनिक ढांचे से जोड़ने का अवसर मिलेगा। लेकिन इस पद की सफलता इस बात से तय होगी कि सीईओ कितनी स्वतंत्रता से काम कर पाते हैं, वित्तीय प्रक्रियाओं को कितना पारदर्शी बनाया जाता है और अनियमितता सामने आने पर जिम्मेदारी किस स्तर तक तय होती है। यहां एक और सावधानी जरूरी है। राम मंदिर को लेकर हर घटना को राजनीतिक चश्मे से देखना भी उचित नहीं होगा। मंदिर की व्यवस्था पर सवाल उठाना रामलला की आस्था पर सवाल उठाना नहीं है। बल्कि इसके उलट, राम के मंदिर को भ्रष्टाचार और अव्यवस्था से मुक्त रखने की मांग स्वयं राम के आदर्शों के अनुरूप है। रामराज्य की कल्पना में न्याय, मर्यादा और जवाबदेही केंद्रीय तत्व हैं। इसलिए अब जरूरत केवल सीईओ नियुक्त करने की नहीं, बल्कि मंदिर प्रशासन में एक ऐसी रामलला आडिट व्यवस्था विकसित करने की है, जिसमें नियमित स्वतंत्र आडिट हो, डिजिटल रिकार्ड सुरक्षित रहें, चढ़ावे की गिनती और जमा करने की पूरी प्रक्रिया कैमरों और तकनीकी निगरानी में हो तथा वित्तीय रिपोर्ट का आवश्यक हिस्सा श्रद्धालुओं के सामने रखा जाए, जिस मंदिर के निर्माण ने भारत की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा दी है, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था भी देश के लिए उदाहरण बननी चाहिए। अयोध्या केवल भव्यता का प्रतीक न बने, बल्कि सुशासन और पारदर्शिता का माडल भी बने। चढ़ावे में चोरी की घटना ने व्यवस्था को आईना दिखाया है। सीईओ की नियुक्ति उस आईने को हटाने के बजाय उसमें दिखाई दे रही कमियों को सुधारने का पहला कदम बने यही अपेक्षा है। रामलला के दरबार में श्रद्धा का हिसाब नहीं मांगा जाता, लेकिन श्रद्धा से आए धन का हिसाब जरूर साफ होना चाहिए। क्योंकि मंदिर की पवित्रता केवल उसके गर्भगृह में नहीं, उसकी व्यवस्था की नीयत में भी दिखाई देती है।

ऑपरेशन हॉटस्पॉट: साइबर अपराधियों..

◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

इंटेलिजेंस और प्रतिबिम्ब मैप : 01 से 31 जुलाई तक चलाए गए तकनीकी विश्लेषण और डेटा इंटेलिजेंस के आधार पर हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई थी। इसके लिए आई 4सी द्वारा विकसित प्रतिबिंब मैप (जीआईएस -आधारित रियल-टाइम मैपिंग) का इस्तेमाल किया गया। सीआईएआर (साइबर इन्वेस्टिगेशन असिस्टेंस रिक्वेस्ट): वर्ष 2026 में अन्य राज्यों में मौजूद आरोपियों/संदिग्धों के संबंध में बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत 303 नोटिस अन्य राज्यों को भेजे गए, जबकि दूसरे राज्यों से प्राप्त 247 नोटिस उत्तराखंड पुलिस द्वारा तामील कराए गए। ध्23.44 करोड़ की बचत: वर्ष 2026 में 1930 नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन और एनसीआरपी पोर्टल पर मिली 18,749 शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए उत्तराखंड पुलिस ने बैंकों के समन्वय से आम जनता के ध्23.44 करोड़ से अधिक की धनराशि सुरक्षित/होल्ड कराई। व्यापक जन-जागरूकता: प्रदेश में 27 अगस्त को आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में 1,100 से अधिक स्कूलों के 1.75 लाख छात्र-छात्राओं को साइबर सुरक्षा का पाठ पढ़ाया गया, जिसमें पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड श्री दीपम सेठ ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद किया। मनी म्यूल्स की काउंसलिंग: 02 सितंबर को अभियान के अंतिम चरण में चिन्हित मनी म्यूल्स को थानों में बुलाकर काउंसलिंग की गई और साइबर अपराध से दूर रहने की शपथ दिलाई गई।

रणनीतिक 'खामोशी' के पीछे सुलग रही 'चिंगारी'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े मुकदमे को लेकर प्रदेश कांग्रेस फिलहाल सार्वजनिक तौर पर भले ही संयम बरत रही हो, लेकिन पार्टी के भीतर नाराजगी कम नहीं है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का मानना है कि राजनीतिक मुद्दों पर लगातार मुखर रहने वाले राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को केवल कानूनी प्रक्रिया मानकर चुप बैठना पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में यह मामला राजनीतिक टकराव का नया केंद्र बन सकता है। कांग्रेस की चुप्पी को फिलहाल रणनीतिक चुप्पी माना जा रहा है। पार्टी सीधे टकराव में उतरने से पहले कानूनी स्थिति, प्रदेश संगठन की भूमिका और राष्ट्रीय नेतृत्व के अगले कदम को देख रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच इस मामले को लेकर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है।

कांग्रेस का आरोप है कि राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक संदर्भ से अलग करके नहीं देखा जा सकता। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी लगातार केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ होने वाली हर कार्रवाई को कांग्रेस राजनीतिक रूप से भी देखेगी। दूसरी ओर भाजपा का तर्क है कि कानून अपना काम करता है और राजनीतिक नेता होने का अर्थ यह नहीं कि किसी को कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखा जाए। यही वह बिंदु है जहां मामला अदालत से निकलकर राजनीतिक बहस में बदल जाता है। कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह अदालत की प्रक्रिया का सम्मान करते हुए अपने राजनीतिक विरोध को किस तरह जनता के बीच रखती है।

उत्तराखंड में कांग्रेस पहले से ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। ऐसे में राहुल गांधी से जुड़ा मामला प्रदेश संगठन के लिए भी राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने का अवसर बन सकता है। पार्टी यदि इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और

◆लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मुकदमे दर्ज होने से देश में बड़े राजनीतिक टकराव के आसार
◆कांग्रेस का आरोप-मुकदमा राजनीतिक प्रतिशोध, भाजपा का जवाब-कानून के दायरे से कोई ऊपर नहीं
◆सड़क से अदालत तक लड़ाई के संकेत, कांग्रेस के सामने चुनौती, कानूनी मोर्चे को राजनीतिक मुद्दा कैसे बनाए

राजनीतिक प्रतिशोध का मुद्दा बनाती है तो कार्यकर्ताओं को लामबंद करने की कोशिश होगी। कांग्रेस के सामने एक और सवाल हैकृक्या वह इस मुद्दे को प्रदेश के स्थानीय सवालों से जोड़ पाएगी? बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे मुद्दों के बीच राहुल गांधी का मुकदमा पार्टी के लिए कितना बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा, यह उसकी रणनीति पर निर्भर करेगा।

फिलहाल कांग्रेस नेतृत्व की चुप्पी ने ही राजनीतिक अटकलों को जन्म दिया है। पार्टी के भीतर यह सवाल उठ रहा है कि यदि मुकदमे को राजनीतिक कार्रवाई माना जा रहा है तो फिर संगठन सड़क पर कब उतरेगा? कांग्रेस के लिए यह फैसला आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आक्रामकता से मामला केवल कानूनी विवाद के बजाय राजनीतिक टकराव में बदल सकता है और भाजपा को कांग्रेस पर न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाने का मौका मिल सकता है। वहीं पूरी तरह चुप रहने से कार्यकर्ताओं में संदेश जा सकता है कि पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व के मुद्दे पर प्रभावी राजनीतिक प्रतिरोध करने में असमर्थ है।

भाजपा के लिए भी यह मामला कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि कांग्रेस इसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन बनाती है तो भाजपा जवाबी अभियान के जरिए इसे कानून बनाम राजनीति की बहस में बदल सकती है। भाजपा का प्रयास यही रहेगा कि राहुल गांधी के मामले को व्यक्तिगत कानूनी प्रकरण के रूप में रखा जाए, जबकि कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक और राजनीतिक संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर सकती है। यानी असली लड़ाई अदालत से बाहर राजनीतिक नैरेटिव की होगी। राहुल गांधी का मुकदमा कांग्रेस के लिए केवल एक नेता का कानूनी मामला नहीं, बल्कि नेतृत्व, संगठन और राजनीतिक रणनीति की परीक्षा भी बन सकता है। पार्टी को तय करना होगा कि इस मुद्दे पर कितना

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

'20 करोड' का बम : उत्तराखंड में वायरल वीडियो-आडियो ने बढ़ाई सनसनी

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव-2027 से पहले उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के भीतर छिड़ी जंग अब पार्टी की चौखट से निकलकर सोशल मीडिया के मैदान में पहुंच गई है। पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित किए गए आशुतोष नेगी के कथित बयानों और उनसे जुड़े वीडियो-आडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश की क्षेत्रीय राजनीति में सनसनी फैल गई है। सबसे ज्यादा चर्चा उस 20 करोड़ के कथित लेन-देन और राजनीतिक साठगांठ को लेकर है, जिसका आरोप नेगी की ओर से लगाया गया है। यूकेडी ने नेगी को अनुशासनहीनता और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कथित भ्रामक एवं तथ्यहीन बयान देने के आरोप में छह वर्ष के लिए निष्कासित किया है। लेकिन निष्कासन के बाद नेगी के तेवर नरम होने के बजाय और तीखे हो गए हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियो और कथित आडियो को लेकर यूकेडी के समर्थकों से लेकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक बहस तेज है। वायरल सामग्री में नेगी से जुड़े बयानों और पार्टी के भीतर चल रहे विवाद को लेकर अलग-अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो या आडयो की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, इसलिए इनमें किए गए दावों को तथ्य के रूप में नहीं बल्कि आरोप और दावे के तौर पर ही देखा जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में वायरल सामग्री का असर कई बार उसकी सत्यता की जांच से पहले ही दिखाई देने लगता है। यही इस समय यूकेडी के साथ हो रहा है।

नेगी ने आरोप लगाया है कि उन्हें राजनीतिक रूप से निबटाने के लिए 20 करोड़ रुपये की कथित सुपारी का खेल हुआ। उन्होंने इसके लिए यूकेडी के कुछ नेताओं पर राष्ट्रीय दलों के साथ कथित साठगांठ का आरोप भी लगाया है। यही आरोप अब पूरे विवाद का केंद्र बन गया है। क्योंकि यदि आरोप निराधार हैं तो यूकेडी नेतृत्व के सामने उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज

◆निष्कासन के बाद आशुतोष नेगी ने लगाए हैं गंभीर आरोप
◆यूकेडी पर राष्ट्रीय दलों से कथित साठगांठ का किया दावा
◆सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो,सियासी हलचल बढ़ी

करने और स्थिति जनता के सामने रखने की चुनौती है। दूसरी ओर, यदि नेगी अपने आरोपों के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण सामने लाते हैं तो विवाद का राजनीतिक असर कहीं बड़ा हो सकता है। फिलहाल 20 करोड़ रुपये के कथित लेन-देन की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं है।

यूकेडी उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति और राज्य आंदोलन की विरासत से जुड़ा दल है। ऐसे में उसके नेताओं पर राष्ट्रीय दलों से कथित साठगांठ के आरोप सामान्य राजनीतिक बयान से कहीं ज्यादा गंभीर माने जाएंगे। 2027 के चुनाव में यूकेडी खुद को भाजपा और कांग्रेस के विकल्प के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय पार्टी के भीतर से ही नेतृत्व और राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठना संगठन के लिए बड़ी चुनौती है। नेगी प्रकरण ने एक और सवाल खड़ा किया है कि क्या उक्रांद चुनावी जमीन मजबूत करने से पहले अपने घर की राजनीतिक लड़ाई सुलझा पाएगा?

यूकेडी की अनुशासनात्मक कार्रवाई के बावजूद नेगी के तेवर आक्रामक बने हुए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए खुद को अब भी उक्रांद की विचारधारा से जुड़ा बताया है। दूसरी ओर पार्टी का कहना है कि निष्कासन के बाद वह यूकेडी के नाम, झंडे और चुनाव चिह्न का अधिकृत रूप से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी लड़ाई अब केवल एक नेता के पार्टी से बाहर होने की नहीं रही। यह नेतृत्व बनाम असहमति, संगठन बनाम व्यक्तिगत राजनीतिक दावे और क्षेत्रीय दल की विश्वसनीयता की लड़ाई बनती जा रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और आडियो ने इस विवाद को तेजी से जनता तक पहुंचा दिया है। हालांकि वायरल सामग्री की प्रमाणिकता की जांच जरूरी है, लेकिन इससे पैदा हुई राजनीतिक बहस को नजरअंदाज करना यूकेडी के लिए आसान नहीं होगा। 2027 के चुनाव में यदि यूकेडी जनता के बीच तीसरे विकल्प की बात लेकर जाता है तो उसे सबसे पहले यह साबित करना होगा कि उसके फैसले और उम्मीदवार किसी राष्ट्रीय दल की छाया में नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मुद्दों पर स्वतंत्र राजनीतिक लाइन पर खड़े हैं। आशुतोष

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

निर्माण कार्य में लापरवाही पर भड़के विधायक, लगाई फटकार

रुद्रपुर (आरएनएस)। पंडित राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज में 2026-27 सत्र से एमबीबीएस कक्षाएं शुरू कराने की कवायद तेज हो गई है। विधायक शिव अरोरा ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर निर्माण कार्य, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निर्माण कार्य की धीमी गति और खामियां मिलने पर उन्होंने कार्यदायी संस्था पेयजल निगम के अधिकारियों और ठेकेदार के प्रतिनिधि को फटकार लगाई। विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने जीएम नरेंद्र नवानी को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक फर्नीचर लगाने के निर्देश दिए।

तय समय में कार्य पूरा नहीं होने पर जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी। उन्होंने प्राचार्य डॉ. चंद्र प्रकाश भैंसौड़ा को निर्माण कार्य, फर्नीचर, फैकल्टी और स्टाफ की प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विधायक ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक आशुतोष सयाना से फोन पर वार्ता कर मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक फैकल्टी और मानव संसाधन उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने बताया कि एनएमसी में अंतिम आवेदन करने से पहले सभी मानक पूरे करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगले 10 दिनों में बुनियादी कमियां दूर कर आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। निरीक्षण के दौरान डॉ. चंद्र प्रकाश, डॉ. सुमन पांडे, डॉ. राजीव कुमार सिंह, डॉ. सृजन श्रीवास्तव, संदीप राव और मनोज मदान आदि मौजूद रहे।

42 स्कूलों के 6600 बच्चों ने किया भारत को जानो प्रतियोगिता में प्रतिभाग

हल्द्वानी(आरएनएस)। भारत विकास परिषद शाखा हल्द्वानी की ओर से सामान्य ज्ञान आधारित 'भारत को जानो-अखिल भारतीय लिखित प्रतियोगिता' का आयोजन किया गया। शहर के 42 स्कूलों में सुबह 10 बजे से हुई लिखित परीक्षा में करीब 6600 बच्चों ने प्रतिभाग किया। शाखा अध्यक्ष दीपक बख्शी ने बताया कि इस परीक्षा का उद्देश्य बच्चों को देश के गौरवशाली इतिहास, महापुरुषों, वीरांगनाओं और समसामयिक विषयों से अवगत कराना है। 30 मिनट की परीक्षा में धर्म एवं संस्कृति, इतिहास, राजनीति, भूगोल, खेल, साहित्य, विज्ञान और समसामयिक विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। प्रतिभागियों ने ओएमआर शीट पर प्रश्नों के उत्तर अंकित किए।

संयोजक डॉ. मोनिका मित्तल और प्रिया कुमार ने बताया कि शीघ्र ही नगर स्तरीय प्रश्न मंच का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आयोजन में प्रांतीय संयोजक संस्कार भवानी शंकर नीरज, सचिव डॉ. निधि अग्रवाल, कोषाध्यक्ष मनीष अग्रवाल, अमित अग्रवाल, विपुल अग्रवाल, मयंक मित्तल, अमित राजपाल, डॉ. अभिषेक मित्तल, सीमा बख्शी, प्रशांत अग्रवाल, अतुल अग्रवाल, सौम्या अग्रवाल, हेमा बिष्ट, एकता अग्रवाल आदि ने सहयोग किया।

पुरानी शिकायतों पर कार्रवाई न होने से एसडीएम नाराज

बागेश्वर(आरएनएस)। तहसील दिवस में अनुपस्थित रहने पर उप जिलाधिकारी वैभव कांडपाल ने जल निगम के अधिकारियों से तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है। वहीं, दर्ज शिकायतों का एक सप्ताह के भीतर समाधान करने के सख्त निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। तहसील सभागार में आयोजित तहसील दिवस के दौरान एसडीएम ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से पूर्व में दर्ज शिकायतों की कार्रवाई रिपोर्ट और फीडबैक लिया। इस दौरान कई विभागों की ओर से शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं किए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। एसडीएम ने अधिकारियों को शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तहसील दिवस में यूकेडी के ब्लॉक अध्यक्ष अधिवक्ता गिरीश कोरंगा ने जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को सरल बनाने और स्वास्थ्य विभाग व लोक निर्माण विभाग से संबंधित पूर्व शिकायतों का समाधान न होने पर नाराजगी जताई। तैलीहाट की ग्राम प्रधान पूजा मेहरा ने पेयजल कनेक्शन की समस्या उठाई। दूरस्थ क्षेत्र मजकोट-कुनझाली निवासी कैलाश गिरी ने बताया कि जंगली सुअरों ने उनकी फसल और सब्जियों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने वन विभाग से फसल नुकसान का मुआवजा देने और समस्या के समाधान की मांग की। वहीं, गोविंद कंसेरी ने मन्यूड़ा सड़क का मुद्दा उठाया। इस अवसर पर तहसीलदार निशा रानी, कानूनगो मोहन सिंह भाकुनी, एबीईओ हिमांशु सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

सेवा संकल्प के लिए भाजपा ने उतारी 'फौज'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को अब पूरी तरह चुनावी मोड में लाने की कवायद तेज कर दी है। पार्टी ने सेवा संकल्प अभियान को जमीन तक पहुंचाने के लिए मंत्रियों से लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रमुख भाजपा नेताओं तक को जिम्मेदारियां सौंपकर पूरी टीम मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। पार्टी का जोर अभियान को केवल संगठनात्मक कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय इसे सरकार के कामकाज और संगठन की सक्रियता से जोड़कर जनता तक पहुंचाने पर है। भाजपा नेतृत्व ने अभियान की सफलता के लिए जिम्मेदारियां तय करते हुए नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों और गतिविधियों की कमान सौंपी है। सरकार के मंत्री जहां अपने विभागीय कामकाज और सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखने की भूमिका निभाएंगे, वहीं संगठन के पदाधिकारी बूथ और मंडल स्तर तक अभियान की गतिविधियों को गति देने का काम करेंगे।

भाजपा की रणनीति साफ है कि सरकार की उपलब्धियों का संदेश संगठन के नेटवर्क के जरिए घर-घर तक पहुंचाया जाए। इसके लिए मंत्री, विधायक, सांसद, प्रदेश पदाधिकारी, जिला संगठन और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को अभियान से जोड़ने की तैयारी है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि चुनावी वर्ष से पहले सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय ही राजनीतिक संदेश को प्रभावी बना सकता है। इसी कारण अभियान में जनप्रतिनिधियों के साथ संगठन के कार्यकर्ताओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रखी गई है।

सेवा संकल्प अभियान में मंत्रियों को विशेष जिम्मेदारी दिए जाने को भाजपा की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। मंत्रियों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं की जानकारी दें और स्थानीय स्तर पर लोगों

◆सेवा संकल्प अभियान के सहारे चुनावी मोड में बीजेपी, मंत्रियों, दिग्गजों को कमान
◆जमीनी स्तर पर उतरेगी पूरी टीम, सरकार और संगठन मिलकर साधेंगे लक्ष्य
◆सेवा संकल्प के दम पर जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड लेकर जाएगी भाजपा

की समस्याओं को भी सुनें। पार्टी के लिए यह अभियान सरकार और जनता के बीच संवाद बढ़ाने का माध्यम भी है। संगठन की कोशिश है कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों तक सीधे पहुंच बनाई जाए और उनसे फीडबैक लिया जाए।

भाजपा की असली ताकत उसका बूथ स्तर का संगठन माना जाता है। यही वजह है कि सेवा संकल्प अभियान को बूथ तक ले जाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मंडल और जिला स्तर के पदाधिकारियों को अभियान की निगरानी और समन्वय की जिम्मेदारी दी जा रही है। कार्यकर्ताओं के जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों तथा संगठन की सेवा गतिविधियों को जनता के बीच ले जाने की रणनीति बनाई गई है।

राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो सेवा संकल्प अभियान केवल जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अपने संगठन को लगातार सक्रिय रखने और जनता के बीच अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रही है। भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती सरकार के खिलाफ बनने वाली संभावित नाराजगी को समय रहते समझना और उसे दूर करना है। ऐसे में लगातार जनसंपर्क अभियान संगठन को जनता की नब्ज टटोलने का अवसर भी देगा। विपक्ष जहां सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मुद्दों को लेकर सवाल उठा रहा है, वहीं भाजपा सेवा और सरकार की उपलब्धियों को अपने राजनीतिक संदेश का आधार बनाने की तैयारी में है।

पार्टी नेतृत्व की ओर से संगठन को सक्रिय रखने का संदेश स्पष्ट है। चुनाव की घोषणा का इंतजार नहीं करना है, बल्कि उससे पहले ही जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करनी है। मंत्रियों से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों और बूथ कार्यकर्ताओं तक जिम्मेदारी बांटने की रणनीति इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। भाजपा की कोशिश है कि चुनाव आने तक संगठन का हर स्तर सक्रिय रहे और पार्टी के पास सरकार के कामकाज के साथ-साथ जमीनी फीडबैक का मजबूत नेटवर्क मौजूद हो।

उत्तराखंड की राजनीति में 2027 की लड़ाई के लिए दोनों प्रमुख दलों की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस जहां सरकार को घेरने के लिए मुद्दे तलाश रही है, वहीं भाजपा लगातार संगठनात्मक गतिविधियों और जनसंपर्क अभियानों के जरिए अपनी जमीन मजबूत करने में जुटी है। ऐसे में सेवा संकल्प अभियान भाजपा के लिए सिर्फ सेवा का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सरकार-संगठन-कार्यकर्ता को एक साथ मैदान में उतारने की रणनीति भी है। अब सवाल यही है कि भाजपा की यह फौज जनता तक सरकार का संदेश पहुंचाने में कितनी सफल होती है और क्या यह अभियान 2027 की चुनावी जंग में पार्टी के लिए राजनीतिक बढ़त तैयार कर पाता है?

परियोजना निदेशक डीआरडीए टिहरी ने संग्रहण केंद्र का किया निरीक्षण

हमारे संवाददाता

टिहरी। ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना के अंतर्गत विकासखंड जाखणीधार में समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) के माध्यम से संचालित विभिन्न उद्यमों का ज्योति (आईएएस, प्रशिक्षु), परियोजना निदेशक डीआरडीए द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उद्यमों की प्रगति, संचालन एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं सीएलएफ पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान देवभूमि सीएलएफ जाखणीधार की फूड कार्ट, उन्नति सीएलएफ रजाखेत की वे-साइड ईटरीज तथा देवभूमि सीएलएफ जाखणीधार की पोल्ट्री फार्म यूनिट का निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही संगम सीएलएफ के संचालित प्रोसेसिंग यूनिट एवं फूड कार्ट का भी निरीक्षण किया गया। वहीं गोट्री यूनिट हेतु चयनित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही कलेक्शन सेंटर के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया गया।

उन्होंने निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्शन सेंटर के कार्य की डेडलाइन 25 सितंबर निर्धारित की गई है। वहीं उन्नति सीएलएफ के कलेक्शन सेंटर का कार्य शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ करवाने के निर्देश संबंधितों को दिए गए।

इसी क्रम में क्षेत्रपाल सीएलएफ मंदार के एग्री इनपुट सेंटर एवं मशरूम यूनिट का भी निरीक्षण किया गया। फूड कार्ट के संचालन को बरसात के दौरान सुचारू बनाए रखने के लिए टेंट की व्यवस्था करने तथा उत्पादों को बेहतर ढंग से प्रदर्शित करने हेतु डिस्प्ले बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए गए। प्रोसेसिंग यूनिट के निरीक्षण के दौरान संबंधित सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया। उन्होंने उद्यमों में उत्पादों की गुणवत्ता, बेहतर प्रबंधन, प्रभावी संचालन एवं विपणन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, ताकि समुदाय आधारित उद्यमों को और अधिक सुदृढ़ एवं लाभकारी बनाया जा सके। निरीक्षण के दौरान रोशन लाल, खंड विकास अधिकारी, ब्रह्मकांत भट्ट, जिला परियोजना प्रबंधक ग्रामोत्थान (रीप) परियोजना, दिग्विजय, सहायक खंड विकास अधिकारी, बॉबी भट्ट, एम एंड ई, संजय शर्मा, बीएमएम, राजदीप चौहान, आजीविका समन्वयक, रविन्द्र पाल, सहायक प्रसार कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी, संबंधित सीएलएफ स्टाफ एवं स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) की महिलाएं उपस्थित रहीं।

फूलगोभी खाने से मिल सकते हैं ये 5 स्वास्थ्यवर्धक लाभ

फूलगोभी भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। इसका उपयोग कई तरह के व्यंजनों में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब्जी आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? फूलगोभी में विटामिन-सी, विटामिन-के, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को कई लाभ प्रदान कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे इस सब्जी को अपनी डाइट में शामिल करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है।

वजन घटाने में है सहायक : फूलगोभी में कम कैलोरी होती है और यह फाइबर का अच्छा स्रोत भी है, जिससे यह वजन घटाने में मदद कर सकती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को सुधारता है और लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप कम खाते हैं। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की चर्बी को कम करने में भी मदद करते हैं। नियमित रूप से फूलगोभी का सेवन करने से आप अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं।

दिल के स्वास्थ्य के लिए है फायदेमंद : फूलगोभी में ऐसे तत्व होते हैं, जो दिल की बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व धमनियों में सूजन को कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को संतुलित रखते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। इस प्रकार फूलगोभी का सेवन करने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है और दिल स्वस्थ रहता है।

पाचन को कर सकती है बेहतर : फूलगोभी में फाइबर की अधिकता होती है, जो पाचन को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करके पाचन को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं, जो आंत के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे आंत का स्वास्थ्य बेहतर होता है। फूलगोभी का सेवन करने से पाचन में सुधार होता है और आंत का स्वास्थ्य बेहतर रहता है।

कैंसर के खतरे को कम करने में है सहायक : फूलगोभी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कैंसर के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। ये तत्व शरीर में मौजूद हानिकारक तत्वों को दूर करके कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकते हैं। इसके अलावा इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हानिकारक तत्वों से लड़ते हैं और कोशिकाओं को सुरक्षित रखते हैं। हालांकि, फूलगोभी कैंसर का इलाज नहीं है। कैंसर रोगी डॉक्टरी जांच और इलाज को प्रथामिकता दें।

रोग प्रतिरोधक क्षमता को कर सकती है मजबूत : फूलगोभी विटामिन-सी का अच्छा स्रोत होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। विटामिन-सी शरीर की सुरक्षा तंत्र को बढ़ाता है और संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर को हानिकारक तत्वों से बचाते हैं। इस प्रकार फूलगोभी का नियमित सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है और आप बीमारियों से जल्दी बचाव कर सकते हैं।

अपने दिनचर्या में शामिल करें बैडमिंटन, इसे खेलने से मिल सकते हैं कई लाभ

बैडमिंटन एक ऐसा खेल है, जो न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है। यह खेल शरीर को सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शारीरिक सहनशक्ति में भी सुधार होता है। इस खेल के माध्यम से आप अपनी गति, संतुलन और तालमेल को भी सुधार सकते हैं। आइए जानते हैं कि बैडमिंटन खेलने से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद : बैडमिंटन खेलने से दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिससे शरीर में खून का संचार बेहतर होता है। यह खेल दिल की सेहत को बढ़ावा देता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से बचाव कर सकता है। नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने वालों में दिल की बीमारी का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह खेल शरीर में खून के प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे दिल को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और यह स्वस्थ रहता है।

मानसिक तनाव से राहत : बैडमिंटन खेलने से मानसिक तनाव कम होता है। जब आप इस खेल को खेलते हैं तो आपका ध्यान पूरी तरह से खेल पर केंद्रित हो जाता है, जिससे आपके दिमाग को आराम मिलता है। यह खेल खुश रहने वाले हार्मोन का उत्पादन बढ़ाता है, जो आपके मूड को बेहतर बनाता है और तनाव को दूर करता है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है और आप अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं।

वजन नियंत्रित करने में सहायक : बैडमिंटन एक ऐसी एक्सरसाइज है, जो कैलोरी जलाने में बहुत प्रभावी होता है। नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने से आपका वजन नियंत्रित रहता है और मोटापे का खतरा कम होता है। यह खेल शरीर की ऊर्जा को तेज करता है, जिससे शरीर में चर्बी कम होती है और फिटनेस बढ़ती है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलने से शरीर की सहनशक्ति भी बढ़ती है, जिससे आप अधिक सक्रिय और स्वस्थ महसूस करते हैं।

शारीरिक सहनशक्ति में सुधार : बैडमिंटन खेलने से शरीर की सहनशक्ति बढ़ती है। इस खेल को खेलने के दौरान तेज दौड़ना, कूदना और तेजी से शटल को मारना पड़ता है, जिससे मांसपेशियों में मजबूती आती है। नियमित रूप से बैडमिंटन खेलने वालों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और उनका शरीर अधिक सक्रिय रहता है।

सोने के तरीके में छिपे रोग और इलाज

आपने अपने सोने के तरीके पर कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन सोने का तरीका आपको बीमार कर सकता है और यहां तक कि हार्ट बर्न, अल्जाइमर व पार्किंसन जैसे रोग भी दे सकता है। वहीं, सोने का तरीका ही आपको इन बीमारियों से बचा भी सकता है। अगर आप पेट या पीठ के बल सीधा सोने के बजाय तिरछा सोने की आदत डालते हैं, तो अल्जाइमर और पर्किंसंस जैसे न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से बच सकते हैं। हाल ही में ब्रिटने में हुई एक स्टडी में यह खुलासा हुआ है। अध्ययन के मुताबिक, सोने के तरीके से दिमाग में मौजूद हानिकारक केमिकल के निकलने का तरीका भी प्रभावित होता है। ऐसी स्टडी पहले भी अमेरिका सहित कई देशों में हो चुकी है।

लेफ्ट हैंड के सहारे सोने पर हार्ट बर्न से छुटकारा = अगर आपको लेफ्ट हैंड के सहारे सोने की आदत है तो आपको रेग्युलर हार्ट बर्न की समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पा सकते हैं। ब्रिटने में हार्ट पेशंट्स में करीब 20 फीसदी इसी परेशानी के शिकार हैं, देखा गया कि जब वे लेफ्ट हैंड के सहारे सोने लगे तो उन्हें परेशानी से कुछ राहत मिली। उन्होंने बताया कि पहले हार्ट बर्न की शिकायत रात में ज्यादा होती थी, लेकिन अब दिक्कत कम हुई है।

लेकिन बुरे सपने आते हैं

वहीं इस मसले पर तुर्की में हुई एक स्टडी बताती है कि लेफ्ट साइड के सहारे सोने पर रात में बुरे सपने आते हैं। करीब 40 फीसदी लोगों ने इसकी शिकायत की। वहीं अगर राइट हैंड के सहारे सोते हैं तो सिर्फ 14 पर्सेंट लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं। पीठ के बल सोने से पीठ दर्द से राहत = अगर आप पीठ के बल सोते हैं तो ऐसा करने से आपको पीठ दर्द से राहत मिल सकती है। यहां तक कि पीठ के बल सोने से आपकी खूबसूरती भी बढ़ती है। आप इस कंडिशन में ज्यादा आराम महसूस करते हैं।

लेकिन खर्राटे की समस्या

वहीं कई स्टडीज यह बता चुकी हैं कि जो लोग पीठ के बल सोते हैं, उनमें खर्राटे लेने की समस्या बढ़ जाती है और यहां तक कि स्लीप ऐप्निया के शिकार हो सकते हैं।

राइट हैंड के सहारे टेंशन से छुटकारा = अगर आपको तनाव या ब्लड प्रेशर है तो राइट हैंड के सहारे सोने से इस परेशानी से राहत मिल जाती है।

लेकिन नेक पेन की समस्या

आप नेक पेन से परेशान हैं तो राइट हैंड साइड के सहारे सोने से परेशानी और बढ़ जाती है।

किचन से बदबू दूर करने के घरेलू उपाय

क्या आपके किचन से खाना बनाने के बाद महक नहीं निकलती है? खैर, यह निकल जाएगी, लेकिन आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा।

किचन से बासी दुर्गंध को निकालने के लिए आपको कुछ घरेलू उपाय इस आर्टिकल में बताए जा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि, मसालों का इस्तेमाल खाने में करने से उनमें स्वाद आ जाता है लेकिन पूरे घर में उनकी महक भर जाती है, खासकर किचेन में। थोड़ी देर तक यह महक अच्छी लगती है लेकिन थोड़ी देर बाद, दुर्गंध में बदल जाती है।

कई बार घर में घुसते ही बदबू लगती है और जी मिचलाने लगता है। ऐसे में खाना बनाने के बाद, महक को भगाने के लिए अपनाएं कुछ टिप्स:

1. संतरे के छिलके का पानी- एक कटोरे में एक कप पानी लें और इसे धीमी आंच पर गर्म करें। इस पानी में संतरे के छिलके मिला दें1 इसे दो मिनट के लिए उबलने दें और इसमें दालचीनी मिला दें। आप चाहें तो इलायची भी मिला सकती हैं। इस पानी से किचेन की बदबू दूर भाग जाएगी।

2. टोस्ट से भगाएं बदबू- आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह सही बात है कि टोस्ट की महक से किचेन की बदबू दूर भाग जाती है। इसके लिए आपको एक टोस्ट को निकालकर किचेन में यूं ही खुला छोड़ देना है।

3. बेकिंग सोडा- बेकिंग सोडा को बदबू भगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाना बनाने वाली जगह पर बेकिंग सोडा छिड़क देना चाहिए, ताकि बदबू न भरें। इससे जलने की दुर्गंध भी नहीं आती है। 4. नींबू पानी- फ्रिज में बदबू आने लगी हो या किचेन में, नींबू पानी से भरा कटोरा रख दें, बदबू तुरंत दूर भाग जाएगी।

5. सुगर सोप- सी फूड बनाने के बाद बदबू हाथों और किचेन, दोनों से आने लगती है। ऐसे में सुगर सोप से हाथों को धुल लें और किचेन में भी उसे रख दें। इससे बदबू दूर हो जाएगी।

शब्द सामर्थ्य -056

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. संघर्ष, दौड़धूप (उर्दू.) 5. सुपुत्र, लायक पुत्र 7. ताकतवर, बलशाली 9. खुशबू, सुरभि, सुगंध 10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह 12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना 13. यात्रा 15. मृत, जो मर गया हो 16. छोटे कद का, वामन, बौना 18. सांप का सिर, गुण, कला, कौशल 20. निरुत्तर, बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली 24.माता, जननी 25. संतान, औलाद 26. अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी 27. चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे

1.पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित 2. पाकेटमार, जेब काटने वाला 3. समाधान, खेत जोतने का यंत्र 4. औषधालय 6. युक्ति, उपाय 8. गीला, तर, भीगा हुआ 11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना 14. तुरंत, झटपट 15. स्त्री, नारी, अबला 17. एक और एक चौथाई 19. आदमखोर 21. दुनिया, संसार, जग 22. वर्ष की छः ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है 23. बुद्धि, दिमाग।

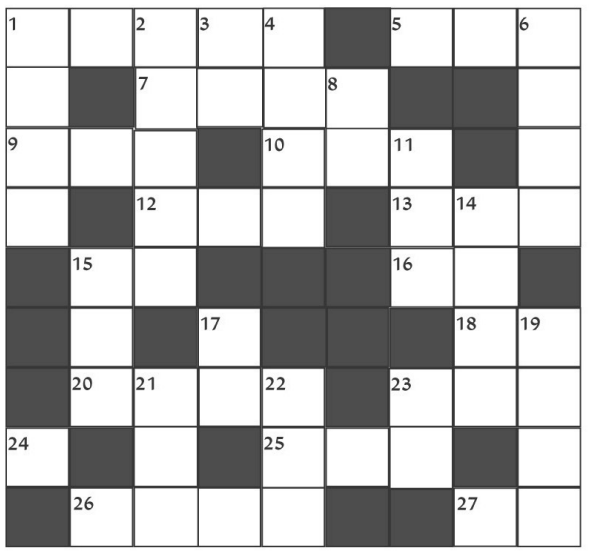

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 55 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म	■	■	स
ट	■	भ	ला	ई	■	अ	स	म
ना	म	■	■	स	मा	धि	■	झ
■	ज	■	बे	■	न	का	र	ना
बा	बू	■	आ	य	क	र	■	■
■	र	की	ब	■	■	■	प्र	था
ज	■	■	रू	प	क	■	ज	न
हा	■	पा	■	ना	म	ची	न	■
ज	हां	प	ना	ह	■	ता	न	ना

यमला पगला दीवाना फिर से के 8 साल: कैसे कृति खरबंदा ने देओल परिवार की इस फ्रेंचाइज़ी में बनाई अपनी अलग पहचान

रिलीज़ के आठ साल बाद भी यमला पगला दीवाना फिर से एक ऐसी फिल्म के रूप में याद की जाती है, जिसने देओल परिवार की दमदार मौजूदगी को फ्रेंचाइज़ी के खास हास्य, रोमांस और पारिवारिक मनोरंजन के साथ पेश किया था। इस जानी-पहचानी दुनिया के बीच कृति खरबंदा का किरदार चिक्कू' एक अलग और ताज़गी भरी ऊर्जा लेकर आई थी, जिसने न सिर्फ दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा, बल्कि अब तक खुद से बांधे रखा है।

हालांकि किसी स्थापित फ्रेंचाइज़ी का हिस्सा बनना अपने आप में एक चुनौती होती है। इसमें भी यमला पगला दीवाना सीरीज़ की अपनी एक मजबूत पहचान थी, जिसे धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल की मौजूदगी ने और भी खास बनाया था। दर्शक पहले से ही फिल्म के बड़े-बड़े हास्य दृश्यों और किरदारों से परिचित थे। ऐसे में कृति ने इस दुनिया में खुद को बेहद सहजता से ढाला और अपनी अलग जगह बनाई। चिक्कू' के रूप में कृति ने कहानी में नई ताज़गी जोड़ी। उनका किरदार देओल परिवार की मस्तीभरी दुनिया का हिस्सा भी बना और अपनी अलग पहचान भी कायम रख पाया। वह सिर्फ कॉमिक माहौल का हिस्सा बनकर नहीं रहीं, बल्कि अपने अभिनय से किरदार को एक अलग व्यक्तित्व दिया। फिल्म में बॉबी देओल के साथ उनकी केमिस्ट्री भी काफी पसंद की गई। दोनों के बीच की सहज और हल्की-फुल्की नोकझोंक ने रोमांटिक ट्रैक को प्रभावी बनाया। कृति की स्क्रीन प्रेजेंस ने कहानी में गर्मजोशी और आकर्षण जोड़ा, जिससे रोमांस और कॉमेडी का संतुलन बना रहा। फिल्म की बड़ी और मनोरंजक दुनिया में खुद को ढालना भी कृति की एक खास उपलब्धि रही। जहां कहानी में हास्य, अराजक परिस्थितियां और बड़े-बड़े मनोरंजक पल थे, वहीं कृति ने अपने अभिनय की स्वाभाविकता बनाए रखी। उनकी अभिव्यक्तियां और सहज स्क्रीन प्रेजेंस ने %चिक्कू' को दर्शकों के लिए यादगार बना दिया।

महत्वपूर्ण बात यह रही कि चिक्कू' सिर्फ एक रोमांटिक किरदार तक सीमित नहीं थी। कहानी को आगे बढ़ाने में भी उसका योगदान था, जिससे कृति को अपने अभिनय का दायरा दिखाने का मौका मिला। रोमांस, कॉमेडी और कहानी में सक्रिय भागीदारी का यही संतुलन उनके किरदार को खास बनाता है। कृति ने फिल्म के संगीत और विजुअल अपील में भी अहम योगदान दिया। उनकी जीवंत स्क्रीन प्रेजेंस, ऊर्जावान परफॉर्मेंस और आकर्षक स्टाइलिंग ने गानों को और भी मनोरंजक बनाया।

फिल्म की उत्सवपूर्ण भावना के साथ उनकी ऊर्जा पूरी तरह मेल खाती थी। आज, आठ साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर यमला पगला दीवाना फिर से कृति खरबंदा के हिंदी फिल्म करियर का एक महत्वपूर्ण पड़ाव नजर आती है। इस फिल्म ने उन्हें एक बड़े कमर्शियल एंटरटेनर का हिस्सा बनने और कॉमेडी, रोमांस तथा पारिवारिक मनोरंजन जैसे अलग-अलग रंगों को निभाने का अवसर दिया। आखिरकार, कृति की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि उन्होंने देओल परिवार की मजबूत पहचान वाली इस फ्रेंचाइज़ी में अपनी अलग जगह बनाई। चिक्कू' के रूप में उन्होंने फिल्म में ताज़गी, आकर्षण और अपनी खास मौजूदगी जोड़ी। यही वजह है कि आठ साल बाद भी उनका यह किरदार फिल्म की यादगार बातों में शामिल किया जाता है।

ऐश्वर्या राजेश और मालविका नायर स्टारर फिल्म महेंद्रगिरि वाराही की रिलीज डेट से उठा पर्दा

अभिनेता सुमथ की आगामी आध्यात्मिक रोमांचक फिल्म महेंद्रगिरि वाराही' इन दिनों दर्शकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। फिल्म को लेकर लगातार किए जा रहे प्रचार अभियान से दर्शकों में उत्सुकता बढ़ रही है। इसी बीच निर्माताओं ने फिल्म की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है। फिल्म 11 सितंबर 2026 को बड़े पैमाने पर सिनेमाघरों में प्रदर्शित की जाएगी।

रिलीज की तारीख की घोषणा के साथ निर्माताओं ने फिल्म में नजर आने वाले सभी प्रमुख कलाकारों को शामिल करते हुए एक नया पोस्टर भी जारी किया है। पोस्टर के जरिए फिल्म की भव्यता और इसके रहस्यमय कथानक की झलक देने की कोशिश की गई है। महेंद्रगिरि वाराही' का निर्देशन संतोष जागरलापुडी कर रहे हैं। फिल्म में ऐश्वर्या राजेश और मालविका नायर मुख्य महिला भूमिकाओं में हैं। फिल्म का संगीत अनूप रूबेन्स ने तैयार किया है। फिल्म में मीनाक्षी गोस्वामी, ब्रह्मानंदम, वेन्नेला किशोर, राजीव कनाकाला और अली भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्माताओं के अनुसार फिल्म की कहानी आध्यात्मिकता, रहस्य और रोमांच के इर्द-गिर्द बुनी गई है।

हाल ही में जारी किए गए फिल्म के प्रचार वीडियो को दर्शकों की ओर से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार को और व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी है। फिल्म का निर्माण कलिपु मधु और लक्ष्मण द्वारा राजश्यामला एंटरटेनमेंट्स और ब्रिज फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है। निर्माताओं ने फिल्म के प्रचार के लिए पारंपरिक और अनोखा तरीका अपनाया है। हैदराबाद के मूसापेट स्थित श्रीरामुलु थिएटर में देवी वाराही की प्रतिमा स्थापित की गई है। इसके साथ ही वाराही गुप्त नवरात्रि समारोह की शुरुआत की गई।

निर्माताओं का कहना है कि आने वाले दिनों में फिल्म के प्रचार अभियान को और तेज किया जाएगा। आध्यात्मिक पृष्ठभूमि, रहस्य और रोमांच से भरपूर महेंद्रगिरि वाराही' के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को देखते हुए इसकी 11 सितंबर की रिलीज पर सभी की नजरें टिकी हैं।

खतरों के खिलाड़ी 15 से जल्दी बाहर होने का दर्द अब भी दिल में है : अविका गौर

अभिनेत्री अविका गौर ने खतरों के खिलाड़ी 15 से अपने एलिमिनेशन के बाद पहली बार अपने अनुभव और भावनाओं के बारे में खुलकर बात की है। शो से इतनी जल्दी बाहर होना उनके लिए आसान नहीं रहा। अविका ने कहा कि एलिमिनेशन के बाद जब वह घर बैठकर शो देखती हैं, तो उनके मन में बार-बार यही ख्याल आता है कि अगर वह उस वक्त वहां होतीं, तो शायद और बेहतर कर सकती थीं।

हालांकि, बाद में उन्हें यह भी एहसास होता है कि टीवी पर बैठकर किसी स्टंट को देखना और खुद उस डर, दबाव और एड्रेनालिन के बीच उसे करना बिल्कुल अलग बात है। अविका गौर ने इंस्टाग्राम पर एक लंबा नोट शेयर किया और बताया कि खतरों के खिलाड़ी ने उनकी जिंदगी और खुद को देखने के नजरिए पर काफी असर डाला है। उन्होंने लिखा, मैंने खतरों के खिलाड़ी देखने के बाद अपने बारे में एक बात महसूस की है। मैं खुद को यह सोचते हुए पाती हूं कि अगर मैं वहां होती, तो मैंने हार नहीं मानी होती। मैं और ज्यादा कोशिश करती। मैं बेहतर करती। अविका ने आगे मजाकिया अंदाज में कहा, शो को आराम से सोफे पर बैठकर देखने के दौरान मुझे ऐसा लगने लगता है, जैसे मैं खतरों के खिलाड़ी की एक्सपर्ट बन गई हूं।

लेकिन फिर याद आता है कि मैं अपनी जिंदगी के आरामदायक माहौल में बैठकर शो देख रही हूं। मुझे न तो उस समय का दबाव महसूस हो रहा है और न ही उस स्टंट को करने का डर। बाहर बैठकर किसी स्थिति का हीरो बनना बहुत आसान है। जब कोई चीज हमारे लिए बहुत मायने रखती है, तो हम उसे बार-बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, अलग-अलग फैसलों की कल्पना करते हैं और कहानी का एक ऐसा वर्जन बना लेते हैं, जो कभी हुआ ही नहीं।

उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार शो किया था, तब मैं सिर्फ 21 साल की थीं। उस समय शो ने मुझे खुद को और अपने भविष्य को एक अलग नजरिए से देखने में मदद की थी। मैं डर का सामना करने और स्टंट करने के इरादे से शो में गई थीं, लेकिन वहां से निकलने के बाद मुझे खुद के बारे में बहुत कुछ नया समझ आया। अविका ने लिखा, मैंने हमेशा मेहनत करने, तैयारी करने, खुद को आगे बढ़ाने और अपनी पसंद की जिंदगी बनाने में विश्वास किया है।

इसलिए ऐसी चीज को स्वीकार करना, जो पूरी तरह मेरे नियंत्रण से बाहर हो, मेरे लिए मुश्किल और सच कहूं तो दिल तोड़ने वाला रहा है। उन्होंने आगे कहा, कई बार इंसान किसी चीज के लिए अपना सब कुछ दे देता है, फिर भी नतीजा वैसा नहीं मिलता जैसा उसने सोचा था। शायद क्लोजर का मतलब यह तय करना नहीं है कि आप शो में बने रहने के लायक थे या आप बेहतर कर सकते थे।

असली क्लोजर यह स्वीकार करना है कि कहानी उस तरह खत्म नहीं हुई, जिस तरह हमने अपने दिमाग में लिखी थी। बता दें कि खतरों के खिलाड़ी 15 में अविका गौर का सफर शो के दूसरे हफ्ते में ही खत्म हो गया था। एलिमिनेशन स्टंट में उनका मुकाबला सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रामानी यानी ओरी से हुआ था।

फिल्म महाकाली में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल श्रिया रेड्डी

बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना की अपकमिंग फिल्म महाकाली की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. फिल्म में अक्षय खन्ना असुरगुरु शुक्राचार्य का रोल प्ले करते नजर आएंगे. वहीं दूसरी तरफ एक्ट्रेस श्रिया रेड्डी महाकाली के रूप में नजर आएंगी. टीजर रिलीज होने के बाद से वो काफी सुर्खियां बटोर रही हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

बता दें, श्रिया रेड्डी साउथ की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. वो एक्स इंडियन टेस्ट क्रिकेटर भरत रेड्डी की बेटी हैं. श्रिया रेड्डी ने अपने करियर की शुरुआत एस एस म्युजिक में एक वीडियो जॉकी के रूप में की थी. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में कदम रखा. श्रिया रेड्डी ने साल 2002 में तमिल फिल्म समुराई से अपने अभिनय सफर की शुरुआत की थी. उन्होंने ब्लैक, थिमिरु, कांचीवरम और प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म सालार जैसी पॉपुलर फिल्मों में काम किया है. सालार ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई की थी.

पर्सनल लाइफ की बात करें तो श्रिया रेड्डी ने 9 मार्च साल 2008 में विक्रम कृष्णा से शादी की है, जो की खुद एक एक्टर हैं. उनकी एक बेटी भी है. श्रिया रेड्डी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 2.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

अब श्रिया रेड्डी महाकाली में धमाल मचाती नजर आने वाली हैं. फिल्म का टीजर हाल ही में रिलीज कर दिया गया है. टीजर में एक्ट्रेस महाकाली के दमदार किरदार में दिखीं. वो गोद में एक छोटे बच्चे को सुलाती नजर आईं.

इस फिल्म को पूजा अपर्णा कोल्लुरु डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म महाकाली अगले साल 8 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मेडिकल कॉलेज की मांग पर निकली जन जागरण रैली

नई टिहरी(आरएनएस)। नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों से चल रहा संयुक्त संघर्ष समिति का धरना अब क्रमिक अनशन में तब्दील हो गया। मांग के समर्थन में 15 सितंबर से समिति ने आरपार की लड़ाई शुरू करने का निर्णय लिया है। मांग पर कार्रवाई ने होने पर उन्होंने जिले में जनप्रतिनिधियों का घेराव करने का निर्णय लिया है। भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य जीतराम भट्ट 31वें दिन भी सत्याग्रह पर बैठे रहेमेडिकल कॉलेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनरतले विभिन्न 44 संगठनों स जुड़े लोग 16 अगस्त से नई टिहरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करने की मांग को लेकर बौराड़ी गणेश चौक में प्रतिदिन धरना कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं। मंगलवार से उन्होंने मांग के समर्थन में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। पहले दिन तिलोक चंद रमोला, जगजीत सिंह नेगी क्रमिक अनशन पर बैठे रहेजीतराम भट्ट, कमल सिंह मेहर व सीपी डबराल सत्याग्रह पर बैठे रहे। धरना स्थल पर हुई बैठक में नागरिक मंच के संरक्षक चंडी प्रसाद डबराल ने कहा कि यदि जल्द मेडिकल कॉलेज बनाने का शासनादेश जारी नहीं किया गया तो 15 सितंबर से आंदोलन को धार देने के लिए जिले में आने वाले जनप्रतिनिधियों का घेराव किया जाएगा। कार्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। इस मौके पर समिति के संयोजक डॉ. राकेश भूषण गोदियाल, भगवानदेवी तोपवाल, नरेंद्र सिंह रावत, जयेंद्र सिंह रावत, दर्शनी रावत, आशा रावत, चतर सिंह चौहान, अमित रतूड़ी, लखवीर सिंह चौहान, सोहन सिंह राणा आदि मौजूद रहे।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभारी बनाने पर जोर

बागेश्वर(आरएनएस)। नमामि गंगे जिला स्तरीय समिति की बैठक में जनपद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार ने नगर निकायों, नगर पालिका, ग्राम पंचायतों और जिला पंचायत के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर स्पष्ट नीति और कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में पूर्व में दिए गए निर्देशों एवं निर्णयों की अनुपालन आख्या की समीक्षा की गई। सीडीओ ने संबंधित विभागों को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डस्टबिनों के ओवरफ्लो होने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसके लिए नियमित सफाई के साथ ही कूड़ा संग्रहण, परिवहन और वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू की जाए। सीडीओ ने नगर पालिका परिषद बागेश्वर को अपशिष्ट निस्तारण के लिए आवश्यक भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। उन्होंने भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने को भी कहा। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी प्रकाश चंद्र आर्या, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या, विवेक परिहार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर विनोद जीना, खंड विकास अधिकारी आलोक भंडारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र.056

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र. 55 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

बड़ी जात में भी सुंग गांव का चौसिंग्या खाडू बनेगा मां नंदा का मार्गदर्शक!

चमोली(आरएनएस)। पांच सितंबर से शुरू होने वाली नंदा देवी बड़ी जात में सुंग गांव के रमेश सिंह बिष्ट का आठ माह का चौसिंग्या खाडू (चार सींगों वाला मेढ़ा) मां नंदा के कैलाश जाने का मार्गदर्शक बनेगा। वर्ष 2014 में भी सुंग गांव से ही चौसिंग्या खाडू मां नंदा का देवरथ बना था।रमेश सिंह ने चार सींगों वाले मेढ़े का जन्म होते ही उसे मां नंदा की जात के लिए समर्पित कर दिया था। पिछले तीन माह तक यह मेढ़ा चीन सीमा क्षेत्र लपथल बुग्याल में चरान के लिए गया था। 28 अगस्त को मेढ़ा सुंग गांव लाया गया। ग्राम प्रधान सुंग तीरथ सिंह बिष्ट का कहना है कि तीन सितंबर को चौसिंग्या खाडू को कुरुड़ मंदिर में ले जाया जाएगा। पांच सितंबर को मां नंदा की कैलाश विदाई में यह मेढ़ा मार्गदर्शक रहेगा। कहा कि 2014 में सुंग गांव के ही केदार सिंह बिष्ट का खाडू मां नंदा का देवरथ बना था।

मां नंदा की जात 12 साल बाद होती है। बड़ी जात के आयोजन से पहले ही क्षेत्र के गांवों में चौसिंग्या खाडू का जन्म हो जाता है। यह चार सींग वाला होता है। इसे मां नंदा का शुभदूत और संदेशवाहक माना जाता है। यह दुर्लभ चार सींगों वाला खाडू लगभग 280 किलोमीटर लंबी कठिन पदयात्रा के दौरान मां नंदा की डोली और भक्तों के सबसे आगे चलता है। लोग खाडू की पीठ पर ओढाए जाने वाले कपड़े पर मां नंदा के लिए श्रृंगार सामग्री, वस्त्र स्थानीय पकवान, कीमती आभूषण बांधते हैं। यात्रा के अंतिम पड़ाव होमकुंड पर पहुंचने के बाद इसे सामग्री सहित कैलाश की ओर अकेला विदा किया जाता है, जहां यह हिमालय की श्रृंखलाओं में आगे जाकर अंतत: विलुप्त हो जाता है।

मां नंदा की बड़ी जात पांच सितंबर को कुरुड़ मंदिर से प्रस्थान कर विभिन्न पड़ावों से होते हुए 12 सितंबर को रामणी गांव पहुंचेंगी। यहां फरस्वाण फाट के जाख देवता, त्यूणा रचकोटी, दशमद्वार काली, बंड, लाता, बदरीनाथ की डोली और छंतोलियों का मिलन होगा। उसके बाद आला, सितेल, कनोल पड़ाव से होते हुए 15 को जात लाटू देवता के मंदिर वाण पहुंचेगी। यहां से जात रणकधार और गैरोली पातल होते हुए 18 सितंबर को वेदनी बुग्याल पहुंचेगी, जहां मां नंदा की सप्तमी की पूजा आयोजित होगी। 19 को जात बगुवावासा, पातर नचौणिंया, कैलवा विनायक, रुपकुंड, ज्योंरागली होते हुए शिलासमुद्र पहुंचेंगे।

20 सितंबर को होमकुंड में मां नंदा की पूजा और चौसिंग्या खाडू की विदाई होगी। उसी दिन श्रद्धालु वापस रात्रि प्रवास के लिए जामुनडाली नामक स्थान में पहुंचेंगे। 30 सितंबर को मां नंदा की डोली सुतोल, पैरी, सितेल, गुलाड़ी, नारंगी, फरखेत पड़ाव होते हुए सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर में पहुंचेगी। इसी के साथ मां नंदा की बड़ी जात का समापन भी हो जाएगा।

जीप व सूमो यूनियन में तीन साल तक नए वाहन नहीं होंगे शामिल

उत्तरकाशी(आरएनएस)। मंदी की मार झेल रहे पुरोला के कमलेश्वर महादेव जीप व सूमो ड्राइवर व ऑनर्स यूनियन ने संगठन में नए वाहनों को शामिल नहीं करने का निर्णय लिया है। यूनियन की बैठक में वाहन कारोबार से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया।यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में यूनियन के अंतर्गत करीब 250 टैक्सियां संचालित हो रही है लेकिन यात्रियों की कमी के कारण कई वाहन स्वामियों को अपनी बारी के लिए एक सप्ताह से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई बार 15 दिनों तक भी वाहन खड़े रहने की स्थिति बन रही हैयूनियन पदाधिकारियों का कहना है कि पुरोला क्षेत्र में टैक्सी कारोबार लगातार कमजोर हो रहा है। कई बार वाहन स्वामियों को केवल यात्रा सीजन शुरू होने का इंतजार करना पड़ता है। वहीं बाजार क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।यूनियन अध्यक्ष यशवीर पंवार और रोटेशन प्रभारी मनमोहन नौडियाल ने बताया कि सभी परिस्थितियों को देखते हुए संगठन ने निर्णय लिया है कि आगामी तीन वर्षों तक यूनियन में किसी भी नए वाहन स्वामी को सदस्यता नहीं दी जाएगी।

भिकियासैंण ब्लॉक प्रमुख उपचुनाव तक क्षेत्र पंचायत बैठक स्थगित करने की मांग

अल्मोड़ा(आरएनएस)। विकासखंड भिकियासैंण के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख के उपचुनाव तक क्षेत्र पंचायत की बैठक स्थगित करने और प्रभारी ब्लॉक प्रमुख से वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वापस लेने की मांग उठाई है। क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक करगेती के नेतृत्व में सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान प्रभारी ब्लॉक प्रमुख एवं ज्येष्ठ उप प्रमुख दिगंबर डंगवाल क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विश्वास खो चुके हैं और उनकी कार्यशैली निरंकुश हो गई है। सदस्यों का आरोप है कि इससे पूर्व भी सोलर लाइट खरीद सहित विभिन्न विकास कार्यों में अनियमितताओं और मनमानी को लेकर शिकायतें की गई थीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ज्ञापन में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार ने मानसून के बाद ब्लॉक प्रमुख का उपचुनाव कराने की बात कही है। ऐसे में उपचुनाव होने तक क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित नहीं की जानी चाहिए, ताकि चुनाव प्रक्रिया किसी प्रकार से प्रभावित न हो।

सदस्यों ने मांग की कि प्रभारी ब्लॉक प्रमुख द्वारा कथित रूप से की जा रही वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितताओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और पंचायत राज अधिनियम के तहत उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार वापस लिए जाएं। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि यदि दो-तिहाई से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त मांगपत्र के बावजूद जिला प्रशासन और पंचायत राज विभाग आवश्यक कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्षेत्र पंचायत सदस्य आगे की रणनीति तय करने को बाध्य होंगे।

ज्ञापन सौंपने वालों में क्षेत्र पंचायत सदस्य दीपक करगेती के साथ भगवती रिखाड़ी, जगत सिंह घुघत्याल, दीपा बिष्ट, नरेंद्र नेगी, कमला देवी, भूपाल सिंह मेहता, रेखा, पूजा असवाल, कविता उप्रेती, त्रिभुवन नेगी, दीपा देवी, पूरन सिंह मावड़ी, चंद्रशेखर, उमराव सिंह सहित अन्य क्षेत्र पंचायत सदस्य शामिल रहे।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में करें आवेदन

नई टिहरी(आरएनएस)। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिले में संचालित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय (केजीबीवी) प्रतापनगर, कौशल और रोतु की बेली में रिक्त सीटों पर आवेदन पत्र मांगे गए हैं। एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग में बीपीएल श्रेणी की इच्छुक छात्राएं छात्रावास के लिए आवेदन कर सकती हैं। केजीबीवी में छात्राओं को शिक्षा निशुल्क प्रदान की जाती है।

मुख्य शिक्षाधिकारी/परियोजना अधिकारी कमला बडवाल ने बताया कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं को पूरी तरह से निशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। जिले में संचालित सात केजीबीवी में बालिकाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय वातावरण और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है।

केजीबीवी अखोड़ी और केजीबीवी प्रतापनगर छात्रावास में कक्षा नौ से कक्षा 12वीं तक, केजीबीवी रौंसाल और केजीबीवी सुजड़गांव में कक्षा छह से कक्षा आठ तक, केजीबीवी आमपाटा, रौतु की बेली और कौशल में कक्षा छह से कक्षा 12वीं तक शिक्षा प्रदान की जा रही है। केजीबीवी प्रतापनगर में अभी 48 सीटें रिक्त है जबकि कौशल में 20 और रौतुकीबेली में आठ सीटें रिक्त हैं। निशुल्क छात्रावास में पढ़ने की इच्छुक पात्र छात्राएं जल्द आवेदन कर सकती हैं। सीईओ ने बताया कि छात्रावास में निशुल्क आवास के साथ ही भोजन, किताबें, यूनिफॉर्म, स्वच्छ पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं दी जा रही है। स्कूलों में आईसीटी लैब, कंप्यूटर, कौशल विकास, गीत-संगीत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलकूद, योग और ओपन जिम की सुविधाएं भी दी जा रही हैं। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए समग्र शिक्षा अभियान की जिला समन्वयक अंजली बुडाकोटी से मोबाइल नंबर 9411747455 पर संपर्क कर सकते हैं।

शिव सेना के राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी ने दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक में लिया भाग

संवाददाता

नई दिल्ली। शिव सेना के राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी ने राज्य प्रमुखा की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में भाग लिया। आज यहां शिवसेना उत्तराखंड के राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी ने नई दिल्ली में आयोजित राज्य प्रमुखों की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया। बैठक की अध्यक्षता शिवसेना के मुख्य नेता एवं महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहेब ने की। इस महत्वपूर्ण बैठक में उत्तराखंड के राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी सहित देश के 20 राज्यों के राज्य प्रमुखों ने भाग लिया। हम सभी को राष्ट्रीय सचिव कैप्टन अभिजीत अडसूल साहेब का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी ने बताया कि बैठक में पंत प्रमुख शिंदे साहेब ने सभी राज्य प्रमुखों को निर्देश दिए कि शिवसेना को अपने जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। राज्य प्रमुख सागर रघुवंशी ने कहा कि पंत प्रमुख शिंदे साहेब के निर्देशों का पालन करते हुए उत्तराखंड में हम बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेंगे और जल्द ही सदस्यता अभियान को अंतिम गांव तक ले जाएंगे।

अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बच्ची की मौत

संवाददाता

देहरादून। अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बच्ची की मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपुर कला निवासी नम्मो ने सहसपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पति अपनी पोती के साथ मोटरसाईकिल से घर की तरफ आ रहे थे जब वह लक्ष्मीपुर के पास पहुंचे तभी अज्ञात वाहन ने उनको अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसके पति गम्भीर रूप से घायल हो गये और उसकी पोती की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

'शुद्धिकरण' विवाद पहुंचा हाईकोर्ट... ◀◀ पृष्ठ 1 का शेष

बैजनाथ की याचिका ने सीधे हाईकोर्ट की चौखट पर खींच लिया है। याचिका ने साफ कर दिया है कि हल्द्वानी में कानून-व्यवस्था का जनाजा ऐसे ही नहीं निकला, बल्कि इसके पीछे नीचे से लेकर ऊपर तक प्रशासनिक नाकामी का पूरा तंत्र शामिल था। याचिका का प्रहार इतना सटीक और मारक है कि इसमें किसी छोटे कर्मचारी को बलि का बकरा बनाने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। सत्ता और पुलिस प्रशासन के पांच सबसे बड़े आकाओं को एक साथ कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सात सितंबर को हाईकोर्ट की बेंच ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए आला अफसरों से हलफनामा मांगा है। इससे कई बड़े अधिकारियों का नपना तय माना जा रहा है। बता दें कि रामलीला मैदान विवाद में अब तक पर्दे के पीछे बैठकर तमाशा देखने वाले अफसरों के पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। पूरे उत्तराखंड की निगाहें अब 7 सितंबर को होने वाले न्यायिक प्रहार पर टिकी हैं। कि क्या हाईकोर्ट राज्य सरकार और पुलिस के शीर्ष आकाओं को समन भेजकर निजी रूप से तलब करेगा? क्या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वालों और उन्हें संरक्षण देने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई का चाबुक चलेगा? हल्द्वानी के रामलीला मैदान से उठा यह बवंडर अब प्रशासनिक दफ्तरों को उखाड़ फेंकने के लिए हाईकोर्ट पहुंच चुका है। 7 सितंबर को यह तय हो जाएगा कि कानून का राज चलेगा या फिर खाकी और खादी की जुगलबंदी यूं ही कानून की धज्जियां उड़ाती रहेगी।

रणनीतिक 'खामोशी' के पीछे सुलग रही.. ◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

आक्रामक होना है और किस सीमा तक इसे चुनावी एजेंडे में शामिल करना है।

अभी कांग्रेस खामोश है, लेकिन यह खामोशी कितने दिन चलेगी, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति में कई बार चुप्पी भी रणनीति होती है और कई बार कमजोरी का संकेत भी। राहुल गांधी के मुकदमे पर कांग्रेस की अगली चाल यह तय करेगी कि पार्टी इसे अदालत की चारदीवारी में रहने देती है या फिर उत्तराखंड की सियासत में इसे नया राजनीतिक मोर्चा बना देती है। फिलहाल कांग्रेस चुप है, कार्यकर्ता नाराज हैं और भाजपा कांग्रेस की अगली चाल का इंतजार कर रही है। सवाल सिर्फ इतना है यह चुप्पी कब टूटेगी और टूटेगी तो कितने जोर से?

'20 करोड' का बम : उत्तराखंड में... ◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

नेगी के आरोपों ने इसी सवाल को सबसे ज्यादा हवा दी है।

20 करोड़ का दावा सच है या सियासी विस्फोट इसका जवाब जांच और प्रमाण देंगे। लेकिन इतना तय है कि वायरल वीडियो-आडियो ने 2027 से पहले यूकेडी के भीतर की आग को सार्वजनिक बहस में जरूर ला दिया है। अब निगाहें इस बात पर हैं कि नेगी अगला खुलासा करते हैं या यूकेडी नेतृत्व इन आरोपों का कोई ठोस जवाब सामने रखता है।

पात्र बुजुर्गों को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए सितंबर में चलेगा विशेष अभियान

संवाददाता

देहरादून जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने अधिकारियों को पात्र बुजुर्गो को पेंशन का लाभ दिलाने के लिए सितंबर में अभियान चलाने के निर्देश दिये।

आज यहां जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। जनपद में कोई भी पात्र बुजुर्ग सामाजिक सुरक्षा के अधिकार से वंचित न रहे, इसके लिए जिला प्रशासन सितंबर माह में वृद्धावस्था पेंशन योजना से वंचित पात्र व्यक्तियों को लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र वृद्धजनों, जिनके परिवार की वार्षिक आय 48 हजार रुपये से अधिक नहीं है, को 1,500 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है। पति-पत्नी दोनों के पात्र होने की स्थिति में परिवार को कुल 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन बैंक खाते के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। जिलाधिकारी ने कहा कि वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा किसी पात्र व्यक्ति के लिए उपकार नहीं, बल्कि उसका अधिकार है।

प्रशासन का प्रयास है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र वृद्धजन तक सम्मानपूर्वक पहुंचे। इसी उद्देश्य से विशेष अभियान के दौरान ऐसे बुजुर्गों को चिन्हित किया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद किसी कारणवश अभी तक वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अभियान के तहत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों में पात्र वृद्धजनों से संपर्क कर उनके पेंशन आवेदन से संबंधित औपचारिकताएं पूरी कराने में सहयोग करेंगे। पात्र व्यक्ति समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव तथा राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा। पात्र वृद्धजनों के चिन्हीकरण और आवेदन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सितंबर माह में ग्राम पंचायतों की विशेष बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण-पत्र सहित निर्धारित औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

श्री मां कात्यायनी ज्ञान करतार आश्रम में धूमधाम से मनाई श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

संवाददाता

ऋषिकेश। श्री मां कात्यायनी ज्ञान करतार आश्रम में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनायी गयी।

आज यहां पुरानी शीशम झाड़ी, मुनि की रेती स्थित श्री मां कात्यायनी ज्ञान करतार आश्रम ट्रस्ट में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव हर्षोल्लास, श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। नन्हे-मुन्ने बच्चों ने भगवान श्रीकृष्ण एवं राधा के स्वरूप में सजकर सभी का मन मोह लिया। वहीं नृत्य प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से समां बांध दिया। लेखन प्रतियोगिता में भी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने बच्चों

का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन बच्चों में भारतीय संस्कृति, धार्मिक परंपराओं एवं नैतिक मूल्यों के प्रति रुचि बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान, मुनि की रेती की चेयरपर्सन नीलम बिजलवान, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, महामंडलेश्वर ईश्वर दास एवं महंत लोकेश दास सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजन में श्री मां कात्यायनी ज्ञान करतार आश्रम ट्रस्ट के ट्रस्टी गुरविंदर सलूजा का विशेष योगदान रहा। उनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। आयोजन में ज्ञान करतार पब्लिक स्कूल की शिक्षिकाओं सुधा तिवारी, किरण, अर्चना, अनुराधा, यशोदा, सोनम, सीमा, मीना, स्वप्निल, सुषमा सहित अन्य शिक्षिकाओं एवं सहयोगियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। समारोह के दौरान बच्चों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। पूरे परिसर में भगवान श्रीकृष्ण के जयकारों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। आयोजकों ने सभी अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं प्रतिभागी बच्चों का कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आभार व्यक्त किया।

बुग्यालों के संरक्षण हेतु एसओपी जारी करने की मांग

संवाददाता

देहरादून। संयुक्त नागरिक संगठन ने वन मंत्री को ज्ञापन सौंप बुग्यालों के संरक्षण हेतु एसओपी जारी करने की मांग की।

आज यहां सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुग्यालों के संरक्षण हेतु एसओपी जारी किए जाने की मांग। संयुक्त नागरिक संगठन द्वारा वनमंत्री सुबोध उनियाल, सचिव वन व प्रमुख वन संरक्षक को लिखे गए पत्रों में कहा गया है की उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बुग्यालों(मखमली घास के मैदानों)का संरक्षण पर्यावरण,जैव-विविधता और आजीविका तीनों के लिए बेहद आवश्यक है।यहां अनियंत्रित मानवीय दखल और पर्यटकों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से इनकी प्राकृतिक सुंदरता और मिट्टी की सेहत बिगड़ रही है।भूस्खलन और भू-कटाव के उपायों के अन्तर्गत अनियोजित पर्यटन और ढलान पर गलत गतिविधियों के कारण कई बुग्याल दरक रहे हैं और

भू-कटाव बढ़ रहा है।इन विषयों को रेखांकित करते हुए कहा गया है की बुग्याल जल स्रोतों का संरक्षण करते हैं।ये घास के मैदान प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करते हैं जो वर्षा और पिघलती बर्फ के पानी को सहेजकर स्थायी जल स्रोत को पोषित करते हैं। इसलिए बुग्यालों में दुर्लभ वन्यजीवों की रक्षा की जानी जरूरी है क्योंकि यहां कस्तूरी मृग,हिम तेंदुआ और अन्य दुर्लभ हिमालयी जीवों के प्राकृतिक आवास हैं और इनके संरक्षण से वन्यजीवों का अस्तित्व सुरक्षित रहता है।पत्र में अनुरोध किया गया है की बुग्यालों में कचरा प्रबंधन के अंतर्गत प्लास्टिक और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे को बुग्यालों में छोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाय। बुग्यालों में कंक्रीट के जंगल न पनप सके इसके लिए यहां स्थायी या पक्के ढांचों के निर्माण की अनुमति बिल्कल नहीं दी जाय।बुग्यालों में इको-टूरिज्म नियमों के पालन हेतु कठोर निर्देश जारी किए जाय।ज्ञापन देने वालो में गिरीश चंद्र भट्ट,ठाकुर शेरसिंह,अवधेश शर्मा,उमेश्वर सिंह रावत, राजीव खनसाली, नरेश चंद्र कुलाश्री, दिनेश भंडारी, डा.राकेश डंगवाल थे।

पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी : मुख्यमंत्री

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पशुपालन विभाग तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग में चयनित 101 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। जिसमें 88 पशुधन प्रसार अधिकारी एवं 13 गन्ना पर्यवेक्षक शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र प्राप्त करना युवाओं के परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। आज से वे उत्तराखण्ड सरकार का अभिन्न हिस्सा बनने के साथ ही जनसेवा की महत्वपूर्ण यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से अपने ज्ञान, ऊर्जा और नए विचारों के माध्यम से शासकीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने तथा अपनी कार्यशैली से उदाहरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए देश का सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। आज सरकारी नौकरियां सिफारिश या पहचान से नहीं, बल्कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा के आधार पर मिल रही हैं। पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवा सरकारी नौकरी पाने में सफल रहे हैं। यह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था और युवाओं को उनकी प्रतिभा के आधार पर अवसर प्रदान करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है।

◆पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के 101 नवनियुक्त कार्मिकों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़े हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में पशुपालन हजारों परिवारों की आजीविका, मातृशक्ति के आर्थिक सशक्तीकरण और गांवों की समृद्धि का महत्वपूर्ण आधार है। राज्य सरकार पशुपालन को रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण विकास का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना और मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन के माध्यम से पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालकों को अनुदान पर गाय, बकरी, भेड़ और मुर्गी पालन की इकाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और बेहतर पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गन्ना किसानों के हितों के प्रति भी प्रतिबद्ध है। गन्ना सर्वेक्षण की व्यवस्था को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया गया है। किसानों को नई तकनीक, उन्नत गन्ना प्रजातियों और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देने के लिए गन्ना क्लीनिक एवं परामर्श केंद्र शुरू किए गए हैं। उत्तराखण्ड में गन्ना किसानों को उत्तर प्रदेश की तुलना में 05 रुपये प्रति कुंतल अधिक गन्ना मूल्य दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्हें किसानों और पशुपालकों से संवाद कर उनकी समस्याओं को समझते हुए समाधान के लिए संवेदनशीलता से कार्य करना होगा। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि आम नागरिक को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। शासकीय कार्यप्रणाली में 'सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि' के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए ईमानदारी, अनुशासन और संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत-2047' के लक्ष्य की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखण्ड भी इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने नवनियुक्त कार्मिकों से सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के निर्माण में अपना शत-प्रतिशत योगदान देने का आह्वान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, खजानदास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक श्रीमती सविता कपूर, दुर्गेश्वर लाल, सचिव एस.एन पाण्डेय एवं अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

सत्यापनः 800 से ज्यादा संदिग्ध आए सत्यापन अभियान के रडार में

सत्यापन न कराने पर कुल 87 व्यक्तियों के कटे चालान

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों एवं एसएसपी नवनीत द्वारा दिए गए निर्देश पर आज सुबह अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा कोतवाली कलियर, कोतवाली नगर हरिद्वार व कोतवाली सिड़कुल क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध साइबर अपराधों को लेकर चयनित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सघन सत्यापन अभियान चलाया गया। सत्यापन अभियान के क्रम में कोतवाली कलियर पुलिस ने कुल 320 सत्यापन किये जिनमें पुलिस एक्ट 30 चालान किये गये जबकि 13 लोगों की कांउसलिंग की गयी है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा कुल 323 सत्यापन किये गये जिनमें पुलिस एक्ट में 22 चालान किये गये जबकि 12 लोगों की काउंसलिग की गयी है। कोतवाली सिड़कुल पुलिस द्वारा कुल 161 सत्यापन किये गये जिनमें पुलिस एक्ट में 35 चालान किये गये जबकि 9 लोगों की काउंसलिग की गयी है।

छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर

संवाददाता

देहरादून। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग ने जनपद के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं।

आज यहां शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। समाज कल्याण विभाग ने जनपद के सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य शिक्षण संस्थानों को पात्र छात्र-छात्राओं के आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन कराने के निर्देश दिए हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं प्राचार्यों को निर्देशित किया है कि छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी पात्र विद्यार्थियों तक पहुंचाते हुए उनके आवेदन समय से ऑनलाइन कराए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम तिथि के बाद किसी पात्र विद्यार्थी के आवेदन से वंचित रहने की स्थिति में संबंधित शिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी तय की जाएगी। विभाग के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) और दिव्यांग वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिलाना प्राथमिकता है। शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के साथ ही उनके सत्यापन और अन्य आवश्यक प्रक्रिया को भी निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रवृत्ति आवेदन अथवा पोर्टल से संबंधित तकनीकी एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षण संस्थानों को आवश्यक दिशा-निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। विद्यार्थियों और संस्थानों की सुविधा के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने शिक्षण संस्थानों से अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना पात्र विद्यार्थियों के आवेदन समय से पूर्ण कराने और उनका सत्यापन सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि कोई भी पात्र विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित न रहे।

पोस्टर बने गुटबाजी का 'अखाड़ा'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। चुनावी तैयारियों के बीच कांग्रेस जिस एकजुटता का दावा कर रही है, जमीन पर तस्वीर उससे अलग दिखाई देने लगी है। पार्टी के भीतर खींचतान और गुटबाजी अब बंद कमरों से निकलकर सड़कों तक पहुंचती नजर आ रही है। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि कुछ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने ही पार्टी नेताओं के पोस्टर फाड़ दिए।

पोस्टर फाड़े जाने की घटना को महज राजनीतिक नाराजगी मानकर नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि चुनावी मौसम में पोस्टर केवल प्रचार सामग्री नहीं होते, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति-संतुलन और स्वीकार्यता का भी संकेत देते हैं। जब कार्यकर्ता विपक्षी दल के पोस्टर हटाने के बजाय अपने ही नेताओं के पोस्टर फाड़ने लगें तो सवाल संगठन की एकजुटता पर ही उठता है। पार्टी नेतृत्व भले ही इसे स्थानीय विवाद बताकर किनारा करे, लेकिन चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदेह हो सकती हैं। कार्यकर्ताओं का संदेश यदि यह जाता है कि पार्टी अपने ही नेताओं को लेकर एकमत नहीं है, तो उसका सीधा असर चुनावी अभियान पर पड़ सकता है।

भाजपा के लिए कांग्रेस की अंदरूनी कलह किसी राजनीतिक अवसर से कम नहीं है। भाजपा लंबे समय से कांग्रेस पर नेतृत्व संकट और गुटबाजी का आरोप लगाती रही है। अब अपने नेताओं के पोस्टर फाड़े जाने की घटना विपक्ष को कांग्रेस पर हमला करने के लिए नया मुद्दा दे सकती है। कांग्रेस के सामने असली चुनौती केवल पोस्टर विवाद को रोकने की नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं के भीतर पैदा हो रही नाराजगी को संभालने की है। चुनाव केवल बड़े नेताओं की सभाओं से नहीं जीते जाते। बूथ पर वही कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लेकर खड़ा होता है, जिसे नेतृत्व पर भरोसा हो।

◆अपने ही नेताओं के पोस्टर फाड़ रहे कांग्रेस नेता,चुनाव से पहले घर की लड़ाई आ गई सड़कों पर, भीतर सब कुछ ठीक होने के दावों पर उठे सवाल

पोस्टर फाड़ने की राजनीति देखने में छोटी घटना लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा संदेश बड़ा है। चुनाव से पहले किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे जरूरी उसकी एकजुटता की छवि होती है। जनता के सामने यदि पार्टी अपने ही नेताओं को लेकर बंटी दिखाई दे तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलता है और कार्यकर्ताओं का उत्साह भी प्रभावित होता है। कांग्रेस को अब तय करना होगा कि वह इस विवाद को स्थानीय कार्यकर्ताओं की नाराजगी मानकर छोड़ती है या इसके पीछे मौजूद असंतोष की तह तक जाती है। क्योंकि विपक्ष के पोस्टर फाड़ना राजनीतिक संघर्ष है, लेकिन अपने ही नेताओं के पोस्टर फाड़ना संगठन के भीतर चल रहे संघर्ष का संकेत। चुनाव की लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई और कांग्रेस के भीतर पोस्टर ही आपसी मुकाबले का मैदान बनने लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हैकृकांग्रेस भाजपा से लड़ेगी या पहले अपने घर की लड़ाई खत्म करेगी?

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।